



: : आयुक्त (अपील्स) का कार्यालय, बस्तु एवं सेवा कर और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क : :
O/O THE COMMISSIONER (APPEALS), GST & CENTRAL EXCISE,



द्वितीय तल, जी एस टी भवन / 2nd Floor, GST Bhavan,
 रस कोर्स रिंग रोड, / Race Course Ring Road,
 राजकोट / Rajkot - 360 001

Tele Fax No. 0281 - 2477952/2441142 Email: commrappl3-cexamd@nic.in

रजिस्ट्रार ऑफ सी. द्वारा : - **DIN-20230264SX000022ZA51**

क	अपील / फाइल नं./ Appeal / File No.	मूल आवेदन / OIO No.	दिनांक/ Date
	GAPPL/COM/STP/1359/2022	77/AC/NS/2021-22	30-03-2022

3/2/22 697

ख अपील आदेश संख्या (Order-In-Appeal No.):

RAJ-EXCUS-000-APP-032-2023

आदेश का दिनांक / Date of Order:	07.02.2023	जारी करने की तारीख / Date of issue:	08.02.2023
------------------------------------	-------------------	--	-------------------

श्री शिव प्रताप सिंह, आयुक्त (अपील्स), राजकोट द्वारा पारित /
 Passed by Shri Shiv Pratap Singh, Commissioner (Appeals), Rajkot.

ग अपर आयुक्त / संयुक्त आयुक्त / उपायुक्त / सहायक आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क / सेवाकर/बस्तु एवं सेवाकर,
 राजकोट / जामनगर / गांधीधाम द्वारा उपरोक्त जारी मूल आदेश से उत्पन्न /
 Arising out of above mentioned OIO issued by Additional/Joint/Deputy/Assistant Commissioner, Central
 Excise/ST / GST, Rajkot / Jamnagar / Gandhidham

घ अपीलकर्ता/प्रतिवादी का नाम एवं पता / Name & Address of the Appellant & Respondent

M/s. Shiy Krupa Drilling Company, At: Kalana, Post Kalana, Taluka- Dhoraji

इस आदेश (आदेश) से अपील कोई व्यक्ति निम्नलिखित तरीके में उपयुक्त प्राधिकारी / प्राधिकरण के समक्ष अपील दायर कर सकता है।/
 Any person aggrieved by this Order-in-Appeal may file an appeal to the appropriate authority in the following way.

(A) सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर अपील विन्यास अधिनियम, 1944 की धारा 35B के अंतर्गत
 एवं वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 86 के अंतर्गत निम्नलिखित अंग्रेजी में की जा सकती है।/
 Appeal to Customs, Excise & Service Tax Appellate Tribunal under Section 35B of CEA, 1944 / Under Section 86
 of the Finance Act, 1994 in English may be made as follows:-

(i) बर्गीकरण मुद्दों से सम्बन्धित सभी मामलों में सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर अपील विन्यास अधिनियम की विशेष पीठ, वेस्ट ब्लॉक नं 2,
 और के.पुरम, नई दिल्ली, को जाननी चाहिए।/
 The special bench of Customs, Excise & Service Tax Appellate Tribunal of West Block No. 2, R.K. Puram, New
 Delhi in all matters relating to classification and valuation.

(ii) उपरोक्त परिच्छेद 1(a) में बताए गए अपील के अलावा सेवा कर अपील सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर अपील विन्यास अधिनियम (सिस्टेट) की
 पश्चिम क्षेत्रीय पीठ, द्वितीय तल, बस्तु एवं सेवा कर भवन अहमदाबाद- 380016 को जाननी चाहिए।/
 To the West regional bench of Customs, Excise & Service Tax Appellate Tribunal (CESTAT) at, 2nd Floor, Bhaumali
 Bhawan, Sarwa Ahmedabad-380016 in case of appeals other than as mentioned in para- 1(a) above

(iii) अपील विन्यास अधिनियम के समान अपील प्रस्तुत करने के लिए केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (अपील) नियमावली, 2001 के नियम 6 के अंतर्गत निम्नलिखित रूप में
 रूप EA-3 को चार प्रतियों में दर्ज किया जाना चाहिए। प्रत्येक प्रतियों में एक एक प्रति के साथ, जहाँ उत्पाद शुल्क की मांग, ब्याज की मांग और लगाया
 गया जुर्माना, रुपये 5 लाख या उससे कम 5 लाख रुपये या 50 लाख रुपये से अधिक हो तो क्रमशः 1,000/- रुपये, 5,000/-
 रुपये, 10,000/- रुपये का निश्चित जमा शुल्क की प्रति संलग्न करें। विधायित शुल्क का भुगतान, संबंधित अपील विन्यास अधिनियम की धारा के
 अंतर्गत उद्देश्य के नाम से किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक द्वारा जारी रजिस्टर्ड बैंक ड्राफ्ट द्वारा किया जाना चाहिए। संबंधित ड्राफ्ट का भुगतान, बैंक की
 उक्त धारा में होना चाहिए जहाँ संबंधित अपील विन्यास अधिनियम की धारा स्थित है। स्वतंत्र आदेश (स्टे ऑर्डर) के लिए आवेदन-पत्र के साथ 500/-
 रुपये का निश्चित शुल्क जमा करना होगा।/
 The appeal to the Appellate Tribunal shall be filed in quadruplicate in form EA-3 / as prescribed under Rule 6 of
 Central Excise (Appeal) Rules, 2001 and shall be accompanied against one which at least should be accompanied
 by a fee of Rs. 1,000/-, Rs. 5,000/-, Rs. 10,000/- where amount of duty demand/interest/penalty/return is upto 5
 Lac, 5 Lac to 50 Lac and above 50 Lac respectively in the form of crossed bank draft in favour of Asst. Registrar
 of branch of any nominated public sector bank of the place where the bench of the Tribunal is situated. Application made for grant of stay shall be accompanied
 by a fee of Rs. 500/-

(iv) अपील विन्यास अधिनियम के समान अपील, वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 86(1) के अंतर्गत सेवाकर नियमावली, 1994, के नियम 9(1) के अंतर्गत
 निम्नलिखित रूप S.T.-5 के चार प्रतियों में की जा सकती है एवं उसके साथ जिस आदेश के विरुद्ध अपील की गयी हो, उसकी प्रति साथ में संलग्न करें (जन्म से
 एक प्रति प्रमाणित होनी चाहिए) और इसमें से कम से कम एक प्रति के साथ, जहाँ सेवाकर की मांग, ब्याज की मांग और लगाया गया जुर्माना, रुपये 5 लाख
 या उससे कम 5 लाख रुपये या 50 लाख रुपये तक अथवा 50 लाख रुपये से अधिक हो तो क्रमशः 1,000/- रुपये, 5,000/- रुपये अथवा 10,000/-
 रुपये का निश्चित जमा शुल्क की प्रति संलग्न करें। विधायित शुल्क का भुगतान, संबंधित अपील विन्यास अधिनियम की धारा के अंतर्गत उद्देश्य के नाम से
 किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक द्वारा जारी रजिस्टर्ड बैंक ड्राफ्ट द्वारा किया जाना चाहिए। संबंधित ड्राफ्ट का भुगतान, बैंक की उक्त धारा में होना चाहिए
 जहाँ संबंधित अपील विन्यास अधिनियम की धारा स्थित है। स्वतंत्र आदेश (स्टे ऑर्डर) के लिए आवेदन-पत्र के साथ 500/- रुपये का निश्चित शुल्क जमा
 करना होगा।/
 The appeal under sub section (1) of Section 86 of the Finance Act, 1994, to the Appellate Tribunal Shall be filed
 in quadruplicate in Form S.T.5 as prescribed under Rule 9(1) of the Service Tax Rules, 1994, and shall be
 accompanied by a copy of the order appealed against (one of which shall be certified copy) and should be
 accompanied by a fee of Rs. 1000/- where the amount of service tax & interest demanded & penalty levied is
 up to 5 Lakhs or less Rs.5000/- where the amount of service tax & interest demanded & penalty levied is more
 than five lakhs but not exceeding Rs. Fifty Lakhs, Rs.10,000/- where the amount of service tax & interest
 demanded & penalty levied is more than fifty Lakhs rupees, in the form of crossed bank draft in favour of the
 Assistant Registrar of the bench of nominated Public Sector Bank of the place where the bench of Tribunal is
 situated. Application made for grant of stay shall be accompanied by a fee of Rs.500/-

(i) वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 86 की उप-धाराओं (2) एवं (2A) के अंतर्गत दर्ज की गयी अपील, सेवाकर नियमवाली, 1994, के नियम 9 (2) एवं 9 (2A) के तहत निर्धारित प्रपत्र S.T.-7 में की जा सकती एवं उसके साथ आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अथवा आयुक्त (अपील), केन्द्रीय उत्पाद शुल्क द्वारा पारित आदेश की प्रतियाँ संलग्न करें (उनमें से एक प्रति प्रमाणित होनी चाहिए) और आयुक्त द्वारा सहायक आयुक्त अथवा उपायुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क/ सेवाकर, को अपीलीय न्यायाधिकरण को आवेदन दर्ज करने का निर्देश देने वाले आदेश की प्रति भी साथ में संलग्न करनी होगी।
The appeal under sub section (2) and (2A) of the section 86 the Finance Act 1994, shall be filed in Form ST-7 as prescribed under Rule 9 (2) & 9(2A) of the Service Tax Rules, 1994 and shall be accompanied by a copy of order of Commissioner Central Excise or Commissioner, Central Excise (Appeals) (one of which shall be a certified copy) and copy of the order passed by the Commissioner authorizing the Assistant Commissioner or Deputy Commissioner of Central Excise/ Service Tax to file the appeal before the Appellate Tribunal.

(ii) सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय प्राधिकरण (सेस्टेट) के प्रति अपीलों के मामले में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम 1944 की धारा 35एफ के अंतर्गत, जो की वित्तीय अधिनियम, 1994 की धारा 83 के अंतर्गत सेवाकर को भी लागू की गई है, इस आदेश के प्रति अपीलीय प्राधिकरण में अपील करते समय उत्पाद शुल्क/सेवा कर मांग के 10 प्रतिशत (10%), जब मांग एवं जुर्माना विवादित है, या जुर्माना, जब केवल जुर्माना विवादित है, का भुगतान किया जाए, बशर्ते कि इस धारा के अंतर्गत जमा कि जाने वाली अपेक्षित देय राशि दस करोड़ रुपये से अधिक न हो।
केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर के अंतर्गत "मांग किए गए शुल्क" में निम्न शामिल है

- (i) धारा 11 बी के अंतर्गत रकम
- (ii) सेनबेट जमा की ली गई गलत राशि
- (iii) सेनबेट जमा नियमावली के नियम 6 के अंतर्गत देय रकम

- बशर्ते यह कि इस धारा के प्रावधान वित्तीय (सं. 2) अधिनियम 2014 के आरंभ से पूर्व किसी अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष विचाराधीन स्थगन अर्ज़ी एवं अपील को लागू नहीं होगा।

For an appeal to be filed before the CESTAT, under Section 35F of the Central Excise Act, 1944 which is also made applicable to Service Tax under Section 83 of the Finance Act, 1994, an appeal against this order shall lie before the Tribunal on payment of 10% of the duty demanded where duty or duty and penalty are in dispute, or penalty, where penalty alone is in dispute, provided the amount of pre-deposit payable would be subject to a ceiling of Rs. 10 Crores,

Under Central Excise and Service Tax, "Duty Demanded" shall include :

- (i) amount determined under Section 11 D;
- (ii) amount of erroneous Cenvat Credit taken;
- (iii) amount payable under Rule 6 of the Cenvat Credit Rules

- provided further that the provisions of this Section shall not apply to the stay application and appeals pending before any appellate authority prior to the commencement of the Finance (No.2) Act, 2014.

(C) भारत सरकार कोपनरीक्षण आवेदन :
Revision application to Government of India:

इस आदेश की पुनरीक्षणयाचिका निम्नलिखित मामलों में, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1994 की धारा 35EE के प्रथमपूरतुक के अंतर्गत अवर सचिव, भारत सरकार, पुनरीक्षण आवेदन इकाई, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, चौथी मंजिल, जीवन् दीप भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001, को किया जाना चाहिए।

A revision application lies to the Under Secretary, to the Government of India, Revision Application Unit, Ministry of Finance, Department of Revenue, 4th Floor, Jeevan Deep Building, Parliament Street, New Delhi-110001, under Section 35EE of the CEA 1944 in respect of the following case, governed by first proviso to sub-section (1) of Section-35B ibid:

(i) यदि माल के किसी नुकसान के मामले में, जहां नुकसान किसी माल को किसी कारखाने से भंडार गृह के पारगमन के दौरान या किसी अन्य कारखाने या फिर किसी एक भंडार गृह से दूसरे भंडार गृह पारगमन के दौरान, या किसी भंडार गृह में या भंडारण में माल के प्रसंस्करण के दौरान, किसी कारखाने या किसी भंडार गृह में माल के नुकसान के मामले में।
In case of any loss of goods, where the loss occurs in transit from a factory to a warehouse or to another factory or from one warehouse to another during the course of processing of the goods in a warehouse or in storage whether in a factory or in a warehouse

(ii) भारत के बाहर किसी राष्ट्र या क्षेत्र को निर्यात कर रहे माल के विनिर्माण में प्रयुक्त कच्चे माल पर भरी गई केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के छूट (रिबेट) के मामले में, जो भारत के बाहर किसी राष्ट्र या क्षेत्र को निर्यात की गयी है।
In case of rebate of duty of excise on goods exported to any country or territory outside India of on excisable material used in the manufacture of the goods which are exported to any country or territory outside India.

(iii) यदि उत्पाद शुल्क का भुगतान किए बिना भारत के बाहर, नेपाल या भूटान को माल निर्यात किया गया है।
In case of goods exported outside India export to Nepal or Bhutan, without payment of duty.

(iv) सुनिश्चित उत्पाद के उत्पादन शुल्क के भुगतान के लिए जो क्रेडिट के अंतर्गत इस अधिनियम एवं इसके विभिन्न प्रावधानों के तहत मान्य की गई है और ऐसे आदेश जो आयुक्त (अपील) के द्वारा वित्त अधिनियम (नं. 2), 1998 की धारा 109 के द्वारा नियत की गई तारीख अथवा समयावधि पर या बाद में पारित किए गए हैं।
Credit of any duty allowed to be utilized towards payment of excise duty on final products under the provisions of this Act or the Rules made there under such order is passed by the Commissioner (Appeals) on or after, the date appointed under Sec. 109 of the Finance (No.2) Act, 1998.

(v) उपरोक्त आवेदन की दो प्रतियां प्रपत्र संख्या EA-8 में, जो की केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (अपील) नियमावली, 2001, के नियम 9 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट है, इस आदेश के संश्लेषण के 3 माह के अंतर्गत की जानी चाहिए। उपरोक्त आवेदन के साथ मूल आदेश व अपील आदेश की दो प्रतियां संलग्न की जानी चाहिए।
The above application shall be made in duplicate in Form No. EA-8 as specified under Rule, 9 of Central Excise (Appeals) Rules, 2001 within 3 months from the date on which the order sought to be appealed against is communicated and shall be accompanied by two copies each of the OIO and Order-in-Appeal. It should also be accompanied by a copy of TR-6 Challan evidencing payment of prescribed fee as prescribed under Section 35-EE of CEA, 1944, under Major Head of Account.

(vi) पुनरीक्षण आवेदन के साथ निम्नलिखित निर्धारित शुल्क की अदायगी की जानी चाहिए।
जहाँ संलग्न रकम एक लाख रुपये या उससे कम हो तो रुपये 200/- का भुगतान किया जाए और यदि संलग्न रकम एक लाख रुपये से ज्यादा हो तो रुपये 1000 -/ का भुगतान किया जाए।
The revision application shall be accompanied by a fee of Rs. 200/- where the amount involved in Rupees One Lac or less and Rs. 1000/- where the amount involved is more than Rupees One Lac.

(D) यदि इस आदेश में कई मूल आदेशों का समावेश है तो प्रत्येक मूल आदेश के लिए शुल्क का भुगतान, उपरोक्त ढंग से किया जाना चाहिये। इस तथ्य के होते हुए भी की निम्न पदों कार्य से बचने के लिए यथास्थिति अपीलीय न्यायाधिकरण को एक अपील या केन्द्रीय सरकार को एक आवेदन किया जाता है।
In case, if the order covers various numbers of order- in Original, fee for each O.I.O. should be paid in the aforesaid manner, notwithstanding the fact that the one appeal to the Appellate Tribunal or the one application to the Central Govt. As the case may be, is filed to avoid scriptoria work if excising Rs. 1 lakh fee of Rs. 100/- for each.

(E) यथासंशोधित न्यायालय शुल्क अधिनियम, 1975, के अनुसूची-I के अनुसार मूल आदेश एवं स्थगन आदेश की प्रति पर निर्धारित 6.50 रुपये का न्यायालय शुल्क टिकट लगा होना चाहिए।
One copy of application or O.I.O. as the case may be, and the order of the adjudicating authority shall bear a court fee stamp of Rs.6.50 as prescribed under Schedule-I in terms of the Court Fee Act, 1975, as amended.

(F) सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण (कार्य विधि) नियमावली, 1982 में वर्णित एवं अन्य संबंधित मामलों को सम्मिलित करने वाले नियमों की और भी ध्यान आकर्षित किया जाता है।
Attention is also invited to the rules covering these and other related matters contained in the Customs, Excise and Service Appellate Tribunal (Procedure) Rules, 1982.

(G) उच्च अपीलीय प्राधिकारी को अपील दाखिल करने से संबंधित व्यापक, विस्तृत और नवीनतम प्रावधानों के लिए, अपीलार्थी विभागीय वेबसाइट www.cbec.gov.in को देख सकते हैं।
For the elaborate, detailed and latest provisions relating to filing of appeal to the higher appellate authority, the appellant may refer to the Departmental website www.cbec.gov.in

अपील आदेश / ORDER-IN-APPEAL

M/s Shiv Krupa Drilling Company, At. Kaslana, Post Kalana, Taluka: Dhoraji-360 410 (hereinafter referred to as the appellant) has filed appeal No.GAPPL/COM/STP/1359/2022 against Order-in-Original No. 77/AC/NS/2021-22 dated 30.03.2022 (hereinafter referred to as 'impugned order') passed by the Assistant Commissioner, Central Excise & CGST, Division-II, Rajkot (hereinafter referred to as 'adjudicating authority').

2. Facts of the case, in brief, are that as per data received from the Income Tax department, the appellant appeared to have received various amounts as consideration for providing taxable service during the period 2015-16. It appeared that the appellant had not obtained Service tax registration and did not pay service tax. Therefore, a show cause notice dated 23.04.2021 was issued to the appellant demanding service tax of Rs.6,39,746/- and proposing penalties under Sections 77 and 78 of the Finance Act, 1994. The adjudicating authority, by the impugned order, confirmed the demand of Rs.6,39,746/- along with interest under Section 75 of the Finance Act 1994 and imposed penalty of Rs.6,39,746/- under Section 78 of the Finance Act 1994. He also imposed penalties of Rs.10,000/- under Section 77(1)(a), Rs.10,000/- under Section 77(1)(c) and Rs.10,000/- under Section 77(2) of the Finance Act, 1994.

3. Being aggrieved, the appellant filed the appeal wherein they, *inter alia*, contended that;

- The services provided by the appellant are covered under Negative List under Section 66D (d) (i) of the Finance Act, 1994. Water is primary and essential for agricultural operations. Drilling of bore well is directly related to agricultural operation related to production of any agricultural produce.
- There is no suppression on the part of the appellant in the present case. Demand of service tax only on the basis of data made available from Income Tax department is not sustainable. They relied upon the case of *Pappu Crane Services in Service Tax Appeal No.70707 of 2018 of Allahabd CESTAT*

The appellant were under a bonafide belief that they were not liable to pay service tax. Therefore, there can be no allegation of suppression of facts in the present case and show cause notice issued beyond the time prescribed under Section 73 of the Finance Act, 1994 is bad in law. They relied upon the following case laws:

- a) *NRC Ltd-2007 (5) STR.308*
- b) *Secretary, Town Hall Committee-2007 (8) STR.170*

Min

- c) *Binlas Suplux Ltd-2007 (7) STR.561*
 - d) *Continental Foundation-2007 (216) ELT.177 (SC)*
 - e) *Padmini Products-1989 (43) ELT.195 (SC)*
 - f) *Tamil Nadu Housing Board-1994 (74) ELT.9 (SC)*
 - g) *Jai Prakash Industries Ltd-2002 (146) ELT.481 (SC)*
- The manner of calculation of the liability is not correct as the consideration received is inclusive of service tax payable. They relied upon the case laws of *Shri Chakra Tyrs-1999 (108) ELT.361* and *Maruti Udyog Ltd-2002 (49) RLT.1 (SC)*.
 - Rate taken for the computation of liability is incorrect. The rate of duty upto 31.05.2015 was 12.36%, from 01.06.2015 to 14.11.2015 was 14% and from 15.11.2015 to 31.03.2016 was 14.5%.
 - The provisions of best judgment assessment even for the valuation of service are attracted only if the concerned person fails to furnish the return or if he fails to assess the tax in accordance with law.
 - Penalty under Section 78 is not imposable since there is no short payment of service tax. For imposing penalty, there should be an intention to evade payment service tax on the part of the assessee. They were under bonafide belief that they were not liable for payment of service tax and there was no intention to evade payment of tax. Therefore, no penalty is imposable.
 - Since the issue involved interpretation of complex legal provisions, imposition of penalty is no warranted.

4. Shri Sharad T. Anada, Chartered Accountant appeared for personal hearing on 24.01.2023 and reiterated the submissions in the appeal. He submitted that the appellant was engaged in bore well digging for agriculturists. The same is under negative list. In this regard, he submitted a set of bills and related documents such as Form 8A & 7/12 of the clients as proof of them being agriculturists. He further submitted that extended period cannot be invoked in absence of any fraud or suppression. Even after invoking extended period, part of the demand gets excluded. The adjudicating authority has taken 14.5% tax rate for entire period whereas rate of 14% and 14.5% were applicable to different parts. The adjudicating authority has also not granted cum duty benefit while passing ex-parte order. He requested to set aside the order-in-original as the activity is not taxable.

5. I have carefully gone through the facts of the case, the impugned order, grounds of appeal in the appeal memorandum. In this regard, I find that, the show cause notice was issued only on the basis of data of income received from the Income Tax department demanding service tax without ascertaining the

Shri

category of service. The adjudicating authority has also not ascertained the nature of service provided by the appellant and no evidence was available with him to hold that the appellant has provided any taxable service. On the other hand, the appellant submitted that the income was received from digging of borewell to agriculturists and submitted Profit and Loss account and related documents such as Form 8A & 7/12 of the clients as proof of the clients being agriculturists. Thus, the issue to be decided is whether the service of drilling bore-wells for agriculturist is exempted from service tax under Section 66D(d)(i) of the Finance Act, 1994 or otherwise. Section 66D(d) of the Finance Act, 1994 reads as under:

"(d) services relating to agriculture or agricultural produce by way of—

(i) agricultural operations directly related to production of any agricultural produce including cultivation, harvesting, threshing, plant protection or testing;

(ii) supply of farm labour;

(iii) processes carried out at an agricultural farm including tending, pruning, cutting, harvesting, drying, cleaning, trimming, sun drying, fumigating, curing, sorting, grading, cooling or bulk packaging and such like operations which do not alter the essential characteristics of agricultural produce but make it only marketable for the primary market;

(iv) renting or leasing of agro machinery or vacant land with or without a structure incidental to its use;

(v) loading, unloading, packing, storage or warehousing of agricultural produce;

(vi) agricultural extension services;

(vii) services by any Agricultural Produce Marketing Committee or Board or services provided by a commission agent for sale or purchase of agricultural produce"

6. Plain reading of the above provision would reveal that it covers services relating to agriculture or agricultural produce by way of agricultural operations directly related to production of any agricultural produce including cultivation, harvesting, threshing, plant protection or testing. Drilling of borewell, in my view, can be considered as an agricultural operation directly related to production of agricultural produce. Irrigation is essential for cultivation of any crop and, therefore, drilling of well is to be considered as an agricultural operation. I also find that by Letter No. F. No. 354/35/2014-TRU, dated 4-3-2014, the Finance Minister has clarified that drilling of borewell for supply of water for production of any agricultural produce is excluded from service tax since it is covered by the scope of negative list entry in Section 66D(d)(i) of the Finance Act, 1994. As such, I hold that demand of service tax on the service of drilling of borewell to agriculturalist is not sustainable. Thus the entire demand of service tax is not sustainable and hence there arises no question of imposing any penalty.

7. In view of the above discussions and findings, I set aside the impugned

[Signature]

order and allow the appeal.

८. अपीलकर्ता द्वारा दर्ज की गई अपील का निपटारा उपरोक्त तरीके से किया जाता है।
8. The appeal filed by the Appellant is disposed off as above

Shiv Pratap Singh
(शिव प्रताप सिंह/ SHIV PRATAP SINGH)
आयुक्त (अपील)/Commissioner (Appeals)

By R.P.A.D.

सेवा में, मेस्सेर्स शिव कृपा ड्रिलिंग कंपनी वि- कलणा, तालुका धोराजी-360 410	To M/s Shiv Krupa Drilling Company, At. Kalana, Post Kalana, Taluka: Dhoraji-360 410
--	---

प्रतिलिपि:-

- 1) मुख्य आयुक्त, वस्तु एवं सेवा कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, गुजरात क्षेत्र, अहमदाबाद।
- 2) प्रधान आयुक्त, वस्तु एवं सेवा कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, राजकोट आयुक्तालय, राजकोट।
- 3) ऊप आयुक्त, वस्तु एवं सेवा कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, रमंडल-II, राजकोट।
- 4) गार्ड फ़ाइल।

*Received
Shiv Pratap Singh
CA. Sharan Anand
A.R.
08/02/2023*